[2008] 13 एस.सी.आर.1027

बिहारी राय

बनाम

बिहार राज्य (अब झारखंड)

(क्रिमिनल अपील संख्या 1536 /2008)

सितम्बर 26,2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860: संख्या 304 (भाग 1) धारा 300 अपवाद 4-मौत का कारण-तीन अभियुक्तों द्वारा-घटना के चश्मदीद गवाह-अभिप्रेरणा-परीक्षण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि धारा 302/34/आईपीसी - उच्च न्यायालय ने धारा 304 (भाग I) के अधीन एक अभियुक्त की दोषसिद्धि में परिवर्तन किया और सह-अभियुक्त को दोषमुक्त किया-दोषी अभियुक्त द्वारा अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः मामले के तथ्यों में, सजा दी गई 304 (भाग I)-सही-जांच-अधिकारियों में से एक से पूछताछ न करना, सूचना देने वाले चश्मदीद गवाह द्वारा अन्य चश्मदीद गवाहों के नामों का उल्लेख न करना और अदालत के समक्ष स्टेशन डायरी प्रविष्टि पेश

न करना मामले के तथ्यों में अभियोजन के लिए घातक नहीं है-निजी रक्षा के अधिकार का दावा भी साबित नहीं हुआ।

धारा 96 से 98 और 100 से 106 - निजी रक्षा का अधिकार - अभ्यास-कब-चर्चा की गई।

अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ-साथ दो सह-अभियुक्तों पर एक व्यक्ति की मौत के लिए मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी ने मृतक पर हमला किया। शोर सुनकर अभियोजन साक्षी-1, जब घटना स्थल के पास आया, तो उसने आरोपी को अपने पिता के साथ मारपीट करते देखा। अभियोजन साक्षी 2,5,6 और 7 घटना के अन्य चश्मदीद गवाह थे। इस घटना का कारण पक्षों के बीच लंबे समय से चली आ रही अनबन बताई गई थी। निचली अदालत ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। आईपीसी की धारा 302/34 के तहत अपराध का दोषी। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को धारा 304 के अधीन एक में बदल दिया भाग I में कि मामला धारा 300 के अपवाद में आता है।

4. दोनों सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।

अपील में, अपीलार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि की मांग इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नहीं की गई थी कि फर्द बयान में, अभियोजन साक्षी-1 ने अभियोजन साक्षी 2,6,8 और 7 के नामों का उल्लेख नहीं किया था; कि हमला निजी बचाव में किया गया था; कि जांच अधिकारियों में से एक की जांच नहीं की गई थी; और स्टेशन प्रविष्टि में दर्ज की गई घटना के बारे में पहली जानकारी कोर्ट में पेश नहीं की गई थी।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहाः

अभिनिर्धारित 1. अभियुक्त को आईपीसी की धारा 304 (भाग I) के तहत सही रूप से दोषी ठहराया गया है। जांच अधिकारियों में से किसी एक की गैर-जांच, किसी भी तरह से अभियोजन संस्करण की विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करती है। अभियोजन साक्षी-1 द्वारा अभियोजन साक्षी-2,6 और 7 के नामों का गैर-उल्लेख भी घातक नहीं है। अपने पिता (मृतक) के रोने की आवाज सुनकर वह घटनास्थल की ओर भाग रहा था। जाहिर है, ध्यान इस बात पर था कि उसके पिता के साथ क्या हो रहा था। किसी भी स्थिति

में, गहन प्रतिपरीक्षा के बावजूद उनके साक्ष्य में कुछ भी नाजुक नहीं था। अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी स्थापित किया गया है कि गाँव में अशांति के बारे में कुछ अस्पष्ट जानकारी से संबंधित स्टेशन डायरी प्रविष्टि, एफआईआर की जगह नहीं ले सकती है। [अनुच्छेद 10,11,12 और 19] [1037, ख ; 1034,घ-छ)

2.1 अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दावा किए गए निजी रक्षा के अधिकार को उचित रूप से खारिज कर दिया गया है। केवल इसलिए कि झगड़ा हुआ था और कुछ अभियुक्तों को चोटें आईं, जो इस मामले में मृत्यु के कारण होने की सीमा तक निजी बचाव का अधिकार प्रदान नहीं करता है। हालाँकि इस तरह के अधिकार को सुनहरे तराजू में नहीं तौला जा सकता है, लेकिन यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के बारे में इतनी गंभीर आशंका में थे कि किए गए विरोध इस हद तक था कि बदला लेना बिल्कुल आवश्यक था। इस संबंध में बहुत ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षी 2, 6 और 7 के साक्ष्य का उल्लेख किया है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि घटना स्थल पर अभियोजन साक्षी 1 के आने

से ठीक पहले मृतकऔर आरोपी के बीच झगड़ा हुआ था। मामले के उस दृष्टिकोण में, उच्च अदालत ने इस दलील को स्वीकार कर लिया कि यह घटना अचानक हुए झगड़े के दौरान हुई थी। [अनुच्छेद 16,17] [1036, ड, ज]

2.2 चोटों की संख्या हमेशा यह निर्धारित करने के लिए एक सुरक्षित मानदंड नहीं होती है कि हमलावर कौन था। यह एक सार्वभौमिक नियम के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि जब भी अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर चोटें होती हैं, तो अनिवार्य रूप से यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्तियों ने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते हुए चोटें पहुंचाई थीं। बचाव पक्ष को आगे यह स्थापित करना होगा कि आरोपी को इस तरह से हुई चोटें निजी बचाव के अधिकार के संस्करण को संभव बनाती हैं। घटना के समय या विवाद के दौरान अभियुक्त द्वारा की गई चोटों की गैर-व्याख्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिधि है। लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों का केवल गैर-स्पष्टीकरण सभी मामलों में अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत उन मामलों पर लागू होता है जहां अभियुक्त को मामूली और सतही चोटें लगी हैं या जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और ठोस है, इतना

स्वतंत्र और उदासीन है, इतना संभावित, सुसंगत और विश्वसनीय है कि यह चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से चूक के प्रभाव से कहीं अधिक है। [अनुच्छेद 13) [1034, छ-ज; 1031, क-ग]

लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य एआईआर 1976 SC 2263- को संदर्भित किया गया।

2.3 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिवचन अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकता। यह विचार करते हुए कि क्या निजी बचाव का अधिकार किसी अभियुक्त के लिए उपलब्ध है, यह प्रासंगिक नहीं है कि क्या उसे हमलावर को गंभीर और प्राणघातक चोट पहुँचाने का मौका मिल सकता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या निजी बचाव का अधिकार किसी अभियुक्त के लिए उपलब्ध है, पूरी घटना की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और इसकी उचित व्यवस्था में देखा जाना चाहिए। [अनुच्छेद 13] [1035, ग-घ] [1035, ग-घ]

2.4 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की याचिका में (i) अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का शरीर या संपत्ति शामिल

है; या (ii) किसी अन्य व्यक्ति का; और अधिकार का प्रयोग शरीर के विरुद्ध किसी अपराध के मामले में और चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अपराधों के मामले में किया जा सकता है। स्वैच्छिक मृत्यु के कारण तक निजी बचाव के अधिकार का दावा करने के लिए, अभियुक्त को यह दिखाना होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो इस आशंका के लिए उचित आधारों को जन्म देती थीं कि या तो मृत्यु या गंभीर चोट उसके कारण होगी। अभियुक्त पर यह दिखाने का भार है कि उसे निजी बचाव का अधिकार था जो मृत्यु के कारण तक फैला हुआ था। [अनुच्छेद 13] [1035, ड; 1035, छ-ज]

2.5 अधिकार प्रारंभ होता है, जैसे ही शरीर को खतरे की उचित आशंका अपराध करने के लिए एक प्रलोभन या खतरे से उत्पन्न होती है, हालांकि अपराध तब तक कारित नहीं की गई होगी, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि उचित आशंका न हो। यह अधिकार तब तक रहता है जब तक शरीर के लिए खतरे की उचित आशंका बनी रहती है। [अनुच्छेद 14] [1036, क-ख] जय देव बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1963 एससी 612; रिज़ान और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, मुख्य सचिव, के माध्यम से छत्तीसगढ़,

रायपुर, छत्तीसगढ़ 2003 (2) एससीसी. 661; सुच्चा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 2003 (7) एससीसी 643-पर भरोसा किया गया।

निर्णय विधि संदर्भ

एआईआर 1976 एससी 2263 का उल्लेख किया अनुच्छेद 13
एआईआर 1963 एससी 612 पर भरोसा किया अनुच्छेद 14
2003 (2) एससीसी 661 पर भरोसा किया अनुच्छेद 15 2003 (7) एससीसी 643 पर भरोसा किया अनुच्छेद 15

आपराधिक अपील संख्या 1536/2008 का

झारखंड के उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 25/1/2006 से, रांची में क्रिमिनल अपील संख्या 51/1998

वरिन्दर कुमार शर्मा अपीलार्थी के लिए।

अनिल कुमार झा उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायमूर्ति

1. मंजूरी दी गई।

2. इस अपील में चुनौती डिवीज़न बेंच के फैसले के लिए है झारखंड उच्च न्यायालय की पीठ ने सह-अभियुक्त व्यक्तियों को बरी करने का निर्देश देते हुए अपीलार्थी को आंशिक रूप से अनुमति दी। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन 1985 के 1980/21 के सत्र मामले संख्या 156 में विद्वत पांचवें अतिरिक्त न्यायाधीश, दुमका द्वारा दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने इसे धारा 304 भाग I आई. पी. सी. में बदल दिया और सात साल की सजा सुनाई गई।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का संस्करण इस प्रकार हैः

रामफाली राय (अभियोजन साक्षी .1) सादरी राय का पुत्र है (यहाँ 'मृतक' के रूप में संदर्भित किया गया है) अपीलार्थी और मृतक के परिवार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दण्ड प्रक्रिया संहिता'*) की धारा 145 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। और कई मुकदमे भी दायर किए गए। दोनों परिवारों के बीच विवाद 1952 से लंबित था और अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना का कारण बताया जाता है।*

28.6.1978 को मृतक अपने नौकर मंटू राय के साथ अपने खेत में रहने चला गया। रामफाली राय अभियोजन साक्षी 1) घर पर रहे और लगभग 9.00 सुबह पर, उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी, "मारो मारो" और घर से बाहर आए और उत्तर की ओर भागने लगे, जहाँ से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ असमंजस में पहुँचकर, उन्होंने अपने पिता, सादरी राय को अभियुक्त-अपीलार्थी बिहारी राय और अन्य दो अभियुक्तों द्वारा पीछा किए जाते हुए पाया। तुलसी राय और घुतरू राय भी उस स्थान पर पाए गए थे। आरोपित बिहारी *राय ने तीन वार किए-दो सिर पर और एक मृतक-सादरी राय के हाथ पर, और मृतक नीचे गिर गया और आरोपी 2 और 3 ने भी लाठी चलाई और उसके बाद तीनों आरोपी वहां से चले गए। इस घटना के साक्षी रामफाली राय (अभियोजन साक्षी 1), होरी राय (अभियोजन साक्षी 2), कुवा राय (अभियोजन साक्षी 5), गोपी राय (अभियोजन साक्षी 6) और जर्मन राय (अभियोजन साक्षी 7) थे। इस बीच, जामा पुलिस स्टेशन में सब-इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिन्हा को सूचना मिली कि गाँव-बरुडीह में कुछ घटना हुई है। उक्त उप-निरीक्षक, स्टेशन डायरी में एक प्रविष्टि करने के बाद, घटना स्थल के लिए रवाना हुए और वहां पहुंचे, जहां फर्द बयान प्रदर्शिनी -5, अभियोजन*

साक्षी 1 द्वारा दिया गया, 3.00 बजे दोपहर पर दर्ज किया गया था। उक्त फर्द बयान को एक शिकायत के रूप में दर्ज किया गया था और उक्त शिकायत की मुद्रित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शिनी 6 है। प्रदर्शिनी 1 उक्त शिकायत, प्रदर्शिनी 5 में रामफाली राय (अभियोजन साक्षी 1) के हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान आरम्भ किया गया और कानूनी जांच की गई थी जो प्रदर्शिनी 2/2 के रूप में चिह्नित है, जिसके दौरान गवाहों की जांच की गई थी। खोजबीन के बाद, डॉक्टर से शव परीक्षण करने के अनुरोध के साथ शव को अस्पताल भेज दिया गया। डॉ. उपेंद्र प्रसाद सिन्हा (अभियोजन साक्षी 9) सिविल सहायक सर्जन, सदर अस्पताल, दुमका ने मृतक बद्री राय के शरीर पर पोस्टमॉर्टम किया और उन्हें निम्नलिखित चोटें मिलीं:

(i) बाएं हाथ के बाहरी हिस्से में 1 " x 1/2" x 1" घाव;

(ii) मस्तिष्क के पदार्थ सहित खोपड़ी की हड्डी के पीछे के बाएं पक्ष को काटने के लिए 8" x 1" x 4" घाव (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में 1-अभिव्यक्ति "हैमेटोमा" और रक्तस्राव नहीं जैसा कि मस्तिष्क के पदार्थ के अंदर डॉक्टर द्वारा अपदस्थ किया गया है;

(iii) मस्तिष्क पदार्थ के अंदर एक बड़े रक्तस्राव के साथ मस्तिष्क पदार्थ सहित खोपड़ी की हड्डी के पीछे के दाहिने हिस्से को काटने वाला घाव 6'x 1' 31/2' (यहां भी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अभिव्यक्ति हेमेटोमा है);

डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम सर्टिफिकेट, जारी किया प्रदर्शिनी 4, के साथ उनकी राय है कि शरीर पर पाई गई चोटें (ii) और (iii) मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त हैं और मृत्यु 36 घंटों के भीतर हुई होगी।

4. जाँच पूरी होने के बाद अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

5. ट्रायल कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों अभियोजन साक्षी 1, 2, 5, 6 और 7 के साक्ष्य पर भरोसा किया और अपीलार्थी और सह-अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी पाया। अपील में, उच्च न्यायालय ने पाया कि आई. पी. सी. की धारा 300 का अपवाद 4 लागू होता है और आई. पी. सी. की धारा 304 भाग-1 के संदर्भ में अपीलार्थी को दोषी ठहराया जाता है और उसे सात साल के लिए कठोर दंड से गुजरने की सजा सुनाई जाती है। हालांकि, सह-अभियुक्त व्यक्तियों को बरी

कर दिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, प्राथमिक स्थिति यह थी कि अभियोजन साक्षी 1 द्वारा दिए गए फर्द बयानमें अभियोजन साक्षी 2, 6 और 7 के नाम नहीं दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह स्वीकार करने के बाद कि घटना अचानक झगड़े के दौरान हुई थी, निचली अदालत को निजी बचाव के अधिकार से संबंधित याचिका को स्वीकार करना चाहिए था।

6. फैसले में अभियुक्त व्यक्तियों को क1, क2 और क3 के रूप में वर्णित किया गया था। वर्तमान अपील क1 द्वारा की गई है।

7. उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन साक्षी 1 का साक्ष्य इस आशय का था कि अपने पिता की चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर वह घर से बाहर आया, उस स्थान की ओर दौड़ा और अपीलार्थी को मृतक पर चोट पहुँचाते पाया। इसलिए, यह संभव था कि अभियोजन साक्षियों 2,6 और 7 की उपस्थिति को नहीं देख सकता था। हालाँकि अभियोजन साक्षी 6 ने सभी चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। जहाँ तक

निजी बचाव के अधिकार से संबंधित याचिका का संबंध है, यह ध्यान देने योग्य है कि उस संबंध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षी 2, 6 और 7 के साक्ष्य का उल्लेख किया। इस प्रभाव से कि घटना से ठीक पहले अभियुक्त और प्रथम मृतक ने गलती की थी और उसके बाद प्रथम अभियुक्त ने मृतक पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया था, जो उसके हाथ में था। उस पृष्ठभूमि में धारा 300 के लिए अपवाद 4 लागू किया गया था।

8. अपील के समर्थन में, उच्च न्यायालय के समक्ष लिए गए रुख को अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दोहराया गया है। दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया।

9. यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता के समक्ष लिए गए पक्ष के अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुसंधान अधिकारी का पूर्व निर्धारित मामले में परीक्षण नहीं किया गया था और घटना के संबंध में पहली जानकारी जो अभिलिखित की गई थी। स्टेशन प्रविष्टि भी न्यायालय में

प्रस्तुत नहीं की गई है। यह भी दलील दी जाती है कि चूंकि निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग किया गया था, इसलिए दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है।

10. जहां तक अभियोजन साक्षी 2,6 और 7 के नाम का उल्लेख न किए जाने के संबंध में स्थिति का संबंध है, यह ध्यान देने योग्य है कि जैसा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षी 1 द्वारा अपने पिता की चीखों को सुनने पर ठीक ही कहा था कि अभियोजन साक्षी 1 घटना स्थल की ओर भाग रहा था। जाहिर है, ध्यान इस बात पर था कि उसके पिता को क्या हो रहा है। किसी भी घटना में, तीखे प्रति- परीक्षण के बावजूद उनके साक्ष्य में कुछ भी नाजुक तथ्य सामने नहीं आया है।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा यह भी स्थापित किया गया है कि स्टेशन डायरी प्रविष्टि गाँव में अशांति के बारे में कुछ अस्पष्ट जानकारी से संबंधित है, जो प्राथमिकी में नहीं हो सकती है।

12. जहाँ तक अनुसंधान अधिकारी की गैर-परीक्षा का संबंध है, यह ध्यान देने योग्य है कि अनुसंधान अधिकारी ने केवल पूछताछ की थी। जाँच रिपोर्ट को बिना किसी आपत्ति

के प्रदर्शित किया गया था और रिपोर्ट की शुद्धता को कोई चुनौती नहीं थी। ऐसा होने पर, अनुसंधान अधिकारी से पूछताछ न करने से जी किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के बयान की विश्वसनीयता को कम नहीं करता है।

13. हमलावर कौन था, यह निर्धारित करने के लिए चोटों की संख्या हमेशा एक सुरक्षित मानदंड नहीं होती है। यह एक सार्वभौमिक नियम के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि जब भी अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर चोटें होती हैं, तो अनिवार्य रूप से यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्तियों ने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते हुए चोटें पहुंचाई थीं। बचाव पक्ष को आगे स्थापित करना होगा कि आरोपी को इस तरह से हुई चोटों से निजी बचाव के अधिकार की संभावना बढ़ जाती है। घटना के समय अभियुक्त को लगे चोटों का का गैर-स्पष्टीकरण यह विवाद के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है। लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों का केवल गैर-स्पष्टीकरण सभी मामलों में अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत उन मामलों में लागू होता है जहां अभियुक्त द्वारा की गई चोटें मामूली और सतही हैं या जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और

ठोस है, इतना स्वतंत्र और निस्वार्थ, इतना संभावित, दृढ़ और विश्वसनीय है, कि यह चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से चूक के प्रभाव से कहीं अधिक है। (देखें: लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य (एआईआर 1976 एससी 2263)। निजी बचाव के अधिकार की याचिका अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकती है। यह विचार करते हुए कि क्या निजी बचाव का अधिकार किसी अभियुक्त के लिए उपलब्ध है, यह प्रासंगिक नहीं है कि क्या उसे हमलावर को गंभीर और प्राणघातक चोट पहुँचाने का मौका मिल सकता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या निजी बचाव का अधिकार किसी अभियुक्त के लिए उपलब्ध है, पूरी घटना की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए और इसकी उचित व्यवस्था में देखा जाना चाहिए। धारा 97 निजी रक्षा के अधिकार के विषय से संबंधित है। निजी रक्षा के अधिकार की याचिका में (i) अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का शरीर या संपत्ति शामिल है; या (ii) किसी अन्य व्यक्ति का; और अधिकार का प्रयोग शरीर के खिलाफ किसी भी अपराध के मामले में किया जा सकता है, और चोरी, डकैती, शरारत या आपराधिक अपराध के मामले में, और संपत्ति के संबंध में इस तरह के अपराधों पर प्रयास। धारा 99 निजी

रक्षा के अधिकार की सीमाएँ निर्धारित करता है। धारा 96 और 98 कुछ अपराधों और कृत्यों के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। धारा 96 से 98 और 100 से 106 के तहत दिया गया अधिकार धारा 99 द्वारा नियंत्रित है। अभियुक्त को स्वैच्छिक रूप से मृत्यु के कारण होने तक निजी बचाव के अधिकार का दावा करने के लिए यह दिखाना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां थीं जो जी को इस आशंका के लिए उचित आधार देती थीं कि या तो मृत्यु या गंभीर चोट उसके कारण होगी। यह दिखाने का भार अभियुक्त पर है कि उसे निजी बचाव का अधिकार था जो मृत्यु के कारण तक फैला हुआ था। आईपीसी की धारा 100 और 101 निजी रक्षा के अधिकार की सीमा और विस्तार को परिभाषित करती है।

14. आईपीसी की धारा 102 और 105 क्रमशः शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के प्रारंभ और निरंतरता से संबंधित हैं। अधिकार शुरू हो जाता है, जैसे ही प्रलोभन या अपराध करने की धमकी से शरीर को खतरे की आशंका उत्पन्न होती है, हालांकि अपराध नहीं किया गया हो सकता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि वह कारण सक्षम आशंका न हो। अधिकार तब तक रहता है जब तक शरीर

के लिए खतरे की उचित आशंका बनी रहती है। जय देव बनाम पंजाब राज्य (एआईआर. 1963 एससी 612) में यह मत व्यक्त किया गया था कि जैसे ही उचित आशंका का कारण गायब हो जाता है और खतरे को या तो नष्ट कर दिया जाता है या रास्ते में डाल दिया जाता है, निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं हो सकता है।

15. उपरोक्त स्थिति को रिज़ान और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, मुख्य सचिव, के माध्यम से छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़ 2003 (2) एससीसी. 661; सुच्चा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 2003 (7) एससीसी 643 में रेखांकित किया गया है।

16. केवल इसलिए कि एक झगड़ा हुआ था और अभियुक्त व्यक्तियों में से कुछ को चोटें आईं, जो इस मामले में मृत्यु का कारण बनने की सीमा तक निजी बचाव का अधिकार प्रदान नहीं करता है। हालांकि इस तरह के अधिकार को सुनहरे तराजू में नहीं तौला जा सकता है, लेकिन यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी व्यक्ति अपने जीवन और सम्पति की सुरक्षा के बारे में इतनी गंभीर

आशंका में थे जो की गई सीमा तक जवाबी कार्रवाई बिल्कुल आवश्यक नहीं थी। इस संबंध में बहुत कम ठोस और विश्वसनीय कोई सबूत नहीं दिया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दावा किए गए निजी बचाव के अधिकार को उचित रूप से खारिज कर दिया गया है।

17. उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षी2, 6 और 7 के साक्ष्य का उल्लेख किया है यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि घटना स्थल पर अभियोजन साक्षी 1 के आने से ठीक पहले मृतक और आरोपी के बीच झगड़ा हुआ था। मामले को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने यह याचिका दायर की कि यह घटना अचानक हुए झगड़े के दौरान हुई थी।

18. जैसा कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय 'क' द्वारा ठीक ही कहा गया है कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का कोई प्रश्न ही नहीं था जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया था।

19. अभियुक्त को धारा 304 भाग 1 आईपीसी के तहत उचित रूप से दोषी ठहराया गया है और हिरासत में दी गई सजा भी किसी भी तरह से अनुचित नहीं लगती है।

20. अपील खारिज होने योग्य है, जिसे हम निर्देशित करते हैं।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद मदन मोहन प्रिय, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।